डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एवं सशक्तीकरणः अन्य पिछड़े वर्गों के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)

दयालबाग आगरा

पीएच०डी० समाजशास्त्र की उपाधि हेतु

शोध प्रबन्ध की संशोधित रूपरेखा

2018

निर्देशिका — शोधार्थी

प्रो० पूर्णिमा जैन — मानवेन्द्र सिंह

विभागः समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान

संकाय प्रमुख — विभागाध्यक्षा

प्रो० एस.पी. श्रीवास्तव — प्रो० पूर्णिमा जैन

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एवं सशक्तीकरण : अन्य पिछड़े वर्गों के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रस्तावना

किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तीकरण कहते है। आज के युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारक है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति ने अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है। आविष्कारों से यंत्रीकरण बढ़ा है और यन्त्रीकरण के फलस्वरूप उत्पादन, उसके साथ–ही–साथ सामाजिक सम्बन्धों, प्रस्थितियों और भूमिकाओं, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में बदलाव आया है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, यातायात और संचार के नवीन साधनों, बिजली, पहिये, अणुशक्ति, आदि के आविष्कार ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने में योगदान दिया है। इन्होंने जहाँ जीवन की सुख–सुविधाओं को बढ़ाने में योगदान दिया है, वहीं कुछ समस्याओं को भी उत्पन्न किया है। वर्तमान में विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकी के कारण समाज में युवा पीढ़ी के अधिकारों और शक्ति में भी वृद्धि हुई है। जिसके तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।

20 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मन्त्रिमंडल की बैठक में भारत को डिजिटल आधार पर सशक्त समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के वृहद एवं महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम 'डिजिटल इंडिया' (Digital India) को स्वीकृति प्रदान की गई तथा 1 जुलाई, 2015 से भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू किया गया है। जो सभी मंत्रालयों और सरकार के हर कोने को स्पर्श करने वाले इस वृहद कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा परिकल्पित किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को डिजिटल साक्षरता देना है, ताकि देश का हर नागरिक डिजिटल दुनिया से सम्बन्धित हो सके। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रकृति परिवर्तनकारी है तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सरकारी

सेवाएँ नागरिकों तक डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकें। सरकारी सेवाओं की डिजिटल रूप में अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने से जहाँ यह कार्यक्रम सार्वजनिक जवाबदेही में अभिवृद्धि करेगा, वहीं यह नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सरल पहुँच उपलब्ध कराकर उन्हें आधुनिकतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ भी प्रदान करेगा।

भारत सरकार पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सामाजिक कल्याण जैसी बुनियादी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से घर–घर तक पहुँचाने का जो महत्वाकांक्षी अभियान चला रही है, यह भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से निपटने, पारदर्शी और प्रभावी शासन उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

वस्तुतः डिजिटल इंडिया कार्यक्रम वर्तमान समय की आवश्यकता बन चुका है। इसकी एक ठोस वजह भी है, कि भारत को सॉफ्टवेयर शक्ति के रूप में वैश्विक ख्याति प्राप्त है, किन्तु इस सच से जुड़ा एक नकारात्मक तथ्य यह भी है कि अभी भी यहाँ नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की डिजिटल माध्यम से उपलब्धता काफी कम है। इसी उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में स्वीकृत 'राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना' (NeGP) ने हालांकि मिशन मोड परियोजनाओं (MMPs) और कोर आईसीटी अवसंरचना विकास के माध्यम से इस दिशा में अच्छी प्रगति की है, परंतु देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और ई–शासन के क्षेत्र में प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यक्रम को और वृहद करते हुए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम में रूपांतरित किया गया है जिससे इस पहल को आगे और गहन संवेग प्राप्त हो सके। साथ ही इसके तहत् अब इलेक्ट्रोनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों, विनिर्माण और रोजगार अवसरों को आच्छादित करते हुए समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने की संकल्पना की गई है।

'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' एक समग्र, सुचिंतित, व्यापक एवं बहुआयामी कार्यक्रम है, जिसके द्वारा समाज को सशक्त किया जा सकता है। सशक्तीकरण का अर्थ व्यापक है, जिसमें व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार आर्थिक, सामाजिक, नागरिक स्वतंत्रता, आय, कौशल, आत्मविश्वास, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य आदि की सुदृढ़ता को शामिल किया जा सकता है। जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुआयामी प्रभाव देखे जा सकते हैं। यहाँ सशक्तीकरण हेतु डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के

विजन क्षेत्र, शासन और मांग पर सेवाओं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण, इस कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र तथा इसके उद्देश्य स्तंभों आदि महत्त्वपूर्ण घटकों को रेखांकित किया जा सकता है।

'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' का विजन

- **प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधा के रूप में बुनियादी ढांचा**

  (Infrastructure as Utility to Every Citizen)

  (i) मुख्य सुविधा के रूप में उच्च गति इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा,

  (ii) विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन एवं प्रमाणन योग्य डिजिटल पहचान

  (iii) मोबाइल फोन और बैंक एकाउंट व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय स्पेस में भागीदारी में समर्थ बनाएंगे

  (iv) अपने क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य सेवा केन्द्र तक आसान पहुँच उपलब्ध होगी

  (v) सार्वजनिक क्लाउड में साझेदारी योग्य निजी स्थान उपलब्ध होगा

  (vi) देश में सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध होगा।

- **मांग पर सेवाएँ तथा शासन**

  (Services on Demand and Governance)

  (i) सभी लोगों को आसान एवं एकल विंडो पहुँच उपलब्ध कराने हेतु विभागों या अधिकार क्षेत्रों तक निर्बाध समेकन

  (ii) ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्मों से सरकारी सेवाएँ वास्तविक समय में उपलब्ध

  (iii) आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड पर सभी नागरिकों को पात्रता उपलब्ध कराई जाएगी

  (iv) व्यवसाय करना सरल करने के उन्नयन हेतु सरकारी सेवाएं डिजिटलीकरण रूपांतरित

  (v) एक सीमा के ऊपर वित्तीय हस्तांतरणों को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाना

(vi) निर्णय समर्थन प्रणालियों एवं विकास हेतु भौगोलिक संचार प्रणाली का उन्नयन।

- **नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण**

  (Digital Empowerment of Citizens)

(i) सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता

(ii) सभी डिजिटल संसाधनों तक सार्वजनिक पहुँच उपलब्ध कराना

(iii) सभी सरकारी दस्तावेज/प्रमाण पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे

(iv) भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता

(v) भागीदारीयुक्त शासन के लिए सहयोगपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म

(vi) क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों के लिए सभी पात्रताओं की पोर्टेबिलिटी।

'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' का क्षेत्र

(i) देश को ज्ञान आधारित भविष्य के लिए तैयार करना

(ii) तीन I.T. : आईटी (Indian Talent) + आईटी (Information Technology) = आईटी (India Tomorrow) को साकार करने हेतु परिवर्तनकारी कदम उठाना

(iii) परिवर्तन हेतु समर्थता के लिए प्रौद्योगिकी को केन्द्र में रखना

(iv) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के द्वारा अनेक विभागों को आच्छादित करके बहुत–सी वर्तमान योजनाओं को पुनर्संचित एवं पुनर्केंद्रित करते हुए परस्पर समन्वित कर समकालिक रूप में क्रियान्वित किया जाएगा

'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के उद्देश्य

1. ब्राडबैंड राजमार्ग (Broadband Highways) की स्थापना (ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में)
2. मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुँच

3. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम–राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन

4. ई–गवर्नेंस : प्रौद्योगिकी के जरिए सरकार में सुधार लाना

5. ई–क्रांति : सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी (इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेशन आदि शामिल)

6. सभी के लिए सूचनाओं की उपलब्धता

7. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का संवर्धन (वर्ष 2020 तक निवल शून्य आयात का लक्ष्य)

8. रोजगारों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

9. अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स (जिसमें संदेशों के लिए आईटी प्लेटफॉर्म, बायोमीट्रिक उपस्थिति, सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई, हॉटस्पॉट्स आदि शामिल)।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने की दिशा में भारत सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में जुलाई, 2015 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 'डिजिटल इंडिया सप्ताह' समारोहपूर्वक मनाया गया, जिसमें देश की 400 से अधिक प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में डिजिटल क्रांति लाने के उद्देश्य से तैयार अनेक डिजिटल आधारित योजनाओं को प्रारंभ किया गया। इनमें भारत नेट (देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों में उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य), डिजिटल लॉकर (आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटलीकृत सहज उपलब्ध हो सकने की प्रणाली) सिस्टम, माईजीओवी डॉट इन का मोबाइल एप, स्वच्छ भारत का एप, ई–हस्ताक्षर फ्रेमवर्क, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आदि शामिल हैं।

रोजगार की दृष्टि से भी डिजिटल इंडिया का विशेष महत्त्व है। गांव स्तर पर जब इसका सघन तंत्र विकसित होगा, तो रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सूचनाओं को भेजने तथा पाने के लिए कम्प्यूटर पर काम करने वाले कुशल युवकों को रोजगार मिलेगा, वहीं छोटे–मोटे अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जैसे–फोटोकॉपी एवं प्रिंट लेने की दुकानें, साइबर कैफे एवं चाय आदि की दुकानें। भरोसेमंद इंटरनेट का संजाल स्थापित होने एवं आधारभूत सुविधाएँ बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में

ई–वाणिज्य माध्यमों के जरिए होने वाली बिक्री का हिस्सा भी बढ़ेगा। ध्यातव्य है कि क्राइसिल के एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में ई–वाणिज्य माध्यमों के जरिए होने वाली बिक्री का महज एक फीसदी हिस्सा गांवों से आता है, जो कि इस पहल के बाद बढ़ेगा। साथ ही गैर–सरकारी कारोबारी संस्थानों की गांवों तक पहुँच बढ़ने से वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। इसका एक लाभ इस रूप में भी सामने आएगा कि कृषकों की उपजों, फलों–सब्जियों, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत् चलाए जा रहे आईटी साक्षरता कार्यक्रमों का लाभ सभी को मिलेगा। डिजिटल रूप से सशक्त भारत में जहाँ साक्षर किसान घर बैठे बीजों और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा, वहीं स्कूलों के केन्द्रीय सर्वर से जुड़ने से 'ई–लर्निंग' को प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार सबको बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके माध्यम से जहाँ सभी सरकारी कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं विविध क्षेत्रों में लाखों नए रोजगार भी सृजित होंगे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को इंडिया में रूपांतरित करेगा।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

विश्वास (2016) ने ***"Digital India : A Unique Step towards E-learning in India"*** शोध पत्र में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में शिक्षा में बदलाव हेतु ई–लर्निंग, ई–गवर्नेंस, मोबाइल कनेक्टिविटी, सूचना एवं संचार तकनीकी को सम्मिलित किया है। ई–लर्निंग के विभिन्न लाभों को रेखांकित किया गया है जिसके अन्तर्गत समय और धन की बचत, विद्यालयों को ब्रॉडबैण्ड से जोड़ना, वर्चुअल क्लास रूम व वाई–फाई सेवाओं से जोड़ने पर बल दिया है। जिसकी सहायता से नवाचार शिक्षा एवं तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है एवं ई–लर्निंग के माध्यम से विभिन्न विद्वानों के नवाचार विचारों का आसानी से अधिगम कर्त्ता तक आदान–प्रदान किया है।

सैफुल्लाह (2016) ने ***"Digital India : the Future of India"*** शोध पत्र में भारत के भविष्य निर्माण में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला है। जिसके अन्तर्गत ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह रहे युवाओं को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़ने पर बल दिया है। लेखक द्वारा यह भी

विश्लेषण किया गया है, कि भारत में 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबरेखा के नीचे रहती है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि उक्त असुविधाओं के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को तय समय अवधि में प्राप्त करना सम्भव नहीं होगा। इसीलिए लेखक ने ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है।

रौड्डा (2016) ने ***"Digital India : Issues & Cure''*** शोध पत्र में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न मुद्दे एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। जिसके अन्तर्गत तीन मुख्य मुद्दे हैं। 1. डिजिटल अवसंरचना का विकास– तीव्र गति से इन्टरनेट सुविधा का अभाव, डिजिटल स्पेस की कमी, साइबर सुरक्षा का अभाव, 2. माँग पर सेवाएँ तथा शासन– ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्मों द्वारा सरकारी सेवाएँ समय के अन्तर्गत उपलब्ध कराना, वित्तीय हस्तान्तरण को इलेक्ट्रोनिक और कैशलेश के लिए प्रशिक्षण का अभाव 3. डिजिटल साक्षरता– लाभार्थी को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं है क्योंकि कम्प्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर आदि सम्बन्धित प्रशिक्षण का अभाव है।

खान (2016) ने ***"Digitization and its impact on Economy"*** शोध पत्र में डिजिटलीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को रेखांकित किया है। जिसके अन्तर्गत सूचना एवं संचार तकनीकी को अर्थव्यवस्था का आधार माना है। डिजिटलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विविध सूचनाओं को डिजिटल स्वरूप में आदान–प्रदान किया जा सकता है। डिजिटलीकरण के द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत रोजगार में वृद्धि तथा जीवन शैली में सुधार एवं ज्ञान में वृद्धि आदि को शामिल किया जा सकता है।

चन्द्रशेखर (2016) ने अपने निबन्ध पत्र ***´´स्मार्ट शहरों में डिजिटल गवर्नेंस'*** योजना पत्रिका में समावेशी विकास व सामाजिक परिवर्तन में डिजीटलीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे वित्तीय समावेशन और सामाजिक बदलाव हुआ है, डिजीटल क्रान्ति से सामाजिक परिवेश बदला है, आर्थिक वृद्धि व सामाजिक बदलाव आया है तथा समावेशी विकास का एजेण्डा भी इससे

निश्चित रूप से आगे बढ़ा है। भारत सरकार ने स्मार्ट शहर योजना में पहले 100 शहरों में डिजिटलीकरण को महत्वपूर्ण कारक भी माना है।

पाण्डेय (2016) ने अपने लेख ***"साइनिंग डिजीटल इण्डिया"*** विज्ञान प्रगति पत्रिका में डिजिटल इंडिया का भारतीय समाज को रूपान्तरण करने में महत्वपूर्ण योगदान है तथा इन्होंने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में नौ क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है। वे नौ क्षेत्र इस प्रकार हैं–

- सभी नागरिकों को टेलीफोन सेवा प्रदान की जाये।
- ई–गवर्नेस तकनीक के माध्यम से प्रशासन में सुधार लाया जायेगा।
- सार्वजनिक इण्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम के तहत इण्टरनेट सेवाएँ मुहैया कराई जाएंगी।
- सड़क हाइवे की तर्ज पर ब्राडबैंड हाइवे से शहरों को जोड़ा जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अधिक नौकरियाँ पैदा की जाएंगी।
- इंफॉर्मेशन फॉर ऑल सेंटर खुलेगा जिससे सभी को विभिन्न जानकारियाँ मुहैया कराई जाएंगी।
- ई–क्रान्ति के तहत विभिन्न सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लोगों को मुहैया कराया जाएगा।
- अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम चलेगा। इसका संबंध स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति से है। इसके द्वारा सभी को समय से आने की नसीहत दी जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन अब देश में ही होगा। इसके तहत सरकार का लक्ष्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए कल–पुर्जों के आयात को शून्य करना है। सरकार चाहती है कि वे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान देश में ही बनें, जिससे कि हमारे युवाओं को ओर रोजगार मिल सकें।

मिश्र (2014) ने अपने निबन्ध पत्र ***"डिजिटल डेमोक्रेसी और नवाचार"*** योजना पत्रिका में प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, से मजबूत हुए भारत का वर्णन करते हुए कहा है कि वर्तमान में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए प्रयासरत है। भारत आई. टी. क्षेत्र में विकसित देशों से भी आगे है जिसके द्वारा भारत वर्तमान में डिजिटलीकरण के द्वारा सशक्त भारत बन रहा है इसी पहल को

आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने डिजीटलीकरण (नवाचार) को महत्व प्रदान किया तथा नवाचार बदलते भारत की आधारशिला है, जिससे भारत का लोकतंत्र भी डिजिटल डेमौक्रेसी की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है।

आनन्द (2012) ने ***"E-Learning and Its Impact on Rural Areas"*** शोध पत्र में ई–लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शिक्षण एवं अधिगम के सहायक के रूप में परिभाषित किया है जिसकी सहायता से सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थिओं को जहाँ शिक्षण सुविधाओं के अभाव को ई–लर्निंग के माध्यम से पूरा किया गया है। लेखक ने ई–लर्निंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे युवाओं का सामाजिक और मानसिक विकास हुआ है।

Thomas (2012) ने अपनी पुस्तक ***"Digital India Understanding information, communication and social change"*** में डिजिटलीकरण का भारत एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वर्णन करते हुए कहा है, कि सूचना प्रौद्योगिकी, ई–गवर्नेश, आई. सी. टी., पब्लिक सैक्टर सॉफ्टवेयर, मोबाइल टेलीफोनी इत्यादि को डिजिटलीकरण के माध्यम से मजबूत एवं सुदृढ़ किया है। भारत जैसे देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ है।

परिमल (2008) ने अपनी पुस्तक ***"समाजशास्त्र सामाजिक अन्तः क्रियाओं का अध्ययन"*** में विभिन्न दृष्टिकोण से सामाजिक अन्तः क्रियाओं का एक व्यवस्थिति अध्ययन किया गया है तथा सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन किया गया है। प्रौद्योगिकी हमारी वर्तमान जीवन शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन की पद्धतियां, विचारधाराएं और हमारी सामाजिक संस्थाएं यांत्रिकीकरण द्वारा गहरे रूप में प्रभावित हैं।

सिंह (2006) ने अपनी पुस्तक ***"समाज दर्शन का सर्वेक्षण"*** में विश्व में बदलती परिस्थितियों एवं परिवर्तित परिवेश का वर्णन करते हुए कहा है कि विश्व के समक्ष उपस्थित जटिल समस्याओं का बौद्धिक, वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष समाधान ढूढंने के अंतर्गत पारिस्थितिकी दर्शन, लिंगीय समानता, धर्म निरपेक्षतावाद, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा प्रगति, आंतकवाद, सामाजिक न्याय जैसे सिद्धान्तों

का समावेश किया गया है जिससे कि दर्शन की प्रासंगिकता बनी रहे। प्रस्तुत पुस्तक में इन सभी सिद्धान्तों का सम्यक रुपेण विवेचन किया गया है।

शोध अन्तराल

'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' से पूर्व भारत में कम्प्यूटर सक्षरता, आधार कार्ड, ई–लर्निंग, डिजिटल हस्ताक्षर आदि योजनाएँ संचालित की गई है जो कम्प्यूटर आधारित योजनाएँ है। जिनसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आधार प्राप्त हुआ है। विभिन्न अनुसंधानों में डिजिटलीकरण के प्रमुख आयामों, उद्देश्यों को रेखांकित किया गया था। परन्तु उपरोक्त योजनाएँ धरातलीय स्तर पूर्णतः सफल नहीं हो सकी हैं। इसकी प्रतिपूर्ति में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया है, परन्तु इसे सफल बनाने में भी कई अवरोध है जैसे पिछड़े वर्गों तक इन्टरनेट पहुँच, मूलभूत डिजिटल सुविधाएँ आदि शामिल है जो शोध का विषय हैं, जिन्हें रेखांकित कर कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है।

समस्या कथन

'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' भारत सरकार का एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सशक्त भारत का निर्माण करना है। सशक्त समाज के निर्माण एवं अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए 'डिजिटलीकरण' मौजूदा दौर की अनिवार्यता बन चुका है। इस अनिवार्यता को समझते हुए ही भारत डिजिटल क्रॉंति की ओर आगे बढ़ रहा है। 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' के माध्यम से भारतवासी उस 'डिजिटल मंच' पर पहुँच रहे हैं, जो पूरी पारदर्शिता के साथ सामान्य जन को सरकार के साथ जोडने का काम कर रहा है। भारत सरकार पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सामाजिक कल्याण जैसी बुनियादी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से घर–घर तक पहुँचाने का जो महत्वाकांक्षी अभियान चला रही है। परन्तु इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अनेक बाधाएं भी है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों में इस कार्यक्रम के प्रति जागरुकता, महत्व आदि का आभाव है इसलिए शोधार्थी द्वारा अध्ययन के महत्व को ध्यान में रखते हुए **'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एवं सशक्तीकरण : अन्य पिछड़े वर्गों के सन्दर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'** को एक शोध विषय के रूप में चयन किया गया है,

जिसके अन्तर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व ई–गवर्नेंस के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जायेगा।

अध्ययन का महत्त्व

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य, ''यह आईटी है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को जोड़ने की क्षमता है। हम 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से एकता के मंत्र को साकार करना चाहते हैं।''

भारत को एक सम्पूर्ण डिजिटल देश में बदलने के लिए 1 जुलाई, 2015 को भारतीय सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की शुरूआत की गयी। सरकारी विभागों और प्रमुख कंपनियों (राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर) के एकीकरण के द्वारा डिजिटल रूप से सशक्त भारतीय समाज के लिए ये एक योजनागत पहल है। भारतीय नागरिकों के लिए आसान पहुँच पर सभी सरकारी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस देश का डिजिटलाईजेशन करना मुख्य कारण है।

भारतीय लोगों के लिए एक जनापयोगी सेवा की तरह पूरे देश में डिजिटल संरचना हो क्यों कि ये तेज गति की इंण्टरनेट पहुँच उपलब्ध करायेग जिससे सभी सरकारी सेवा तक आसान ओर तेज पहुँच हो जायेगी। ये नागरिकों को जीवन पर्यन्त, अनोखा, ऑनलाईन और प्रामणिक रूप से डिजिटल पहचान उपलब्ध करायेगा। ये किसी भी ऑनलाईन सेवा जैसे बैंक खाता संभालना, वित्त प्रबंधन, सुरक्षित और सुनिश्चित साईबर स्पेस, शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि के लिए बेहद कारगर साबित होगा। सुशासन की अत्यधिक माँग और ऑनलाईन सेवा डिजिटलाईजेशन के द्वारा वास्तविक समय में सभी सेवाओं को उपलब्ध करायेगा। डिजिटल रूप से बदली हुई सेवा भी वित्तीय लेन–देन को आसान, इलेक्ट्रॉनिक और बिना नकद के बनाने के द्वारा ऑनलाईन व्यापार करने के लिए लोगों को बढ़ावा देगी। भारतीय लोगों को डिजिटल सशक्तिकरण डिजिटल संसाधनों की वैश्विक पहुँच के द्वारा डिजिटल साक्षरता को वास्तव में मुमकिन बनाएगी। ऑनलाईन प्रमाण–पत्र या जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के लिए ये लोगों को

सक्षम बनायेगी न कि स्कूल, कॉलेज, कार्यालय या किसी संस्थान में भौतिक रूप से प्रस्तुति की जरूरत होगी।

शोध अध्ययन में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

1. **डिजिटल :** डिजिटल एक कम्प्यूटर शब्दावली हैं, जिसका अर्थ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अंकीय प्रयोग है जो बिना रूके निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका मुख्य सम्बन्ध डिजिट या संख्या के रूपांतरण से है।
2. **सशक्तीकरण :** सशक्तीकरण का अर्थ व्यापक है, जिसमें व्यक्ति को निर्णय लेने का अधिकार आर्थिक, सामाजिक, नागरिक स्वतंत्रता, आय, कौशल, आत्मविश्वास, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य आदि की सुदृढ़ता को शामिल किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में सामाजिक सुरक्षा, जनकल्याण सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व ई—गवर्नेंस के क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्गों की जागरुकता एवं अपने दैनिक जीवन में विभिन्न सेवाओं के उपयोग को सशक्तीकरण के रूप में व्यक्त किया जायेगा।
3. **अन्य पिछड़ा वर्ग :** अन्य पिछड़ा वर्ग उन पिछड़ी जातियों का समूह है, जो सरकार द्वारा घोषित हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों का लैंगिक आधार पर सशक्तीकरण का विश्लेषण करना।
2. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों का आयु वर्ग के आधार पर सशक्तीकरण का विश्लेषण करना।
3. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों का शैक्षिक आधार पर सशक्तीकरण का विश्लेषण करना।

4. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में अन्य पिछड़े वर्गों का आय के आधार पर सशक्तीकरण का विश्लेषण करना।
5. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की प्रभावशीलता एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण के सन्दर्भ में एक स्वॉट (SWOT) विश्लेषण करना।

शोध प्रश्न

1. क्या अन्य पिछड़े वर्गों में लिंग के आधार पर डिजिटल सशक्तीकरण के प्रभावों में अन्तर पाया जाता है ?
2. क्या अन्य पिछड़े वर्गों में आयु वर्ग के आधार पर डिजिटल सशक्तीकरण के प्रभावों में अन्तर पाया जाता है ?
3. क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में शैक्षिक आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो के सशक्तीकरण में सार्थक अन्तर पाया जाता है ?
4. क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सन्दर्भ में आय के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो के सशक्तीकरण में सार्थक अन्तर पाया जाता है ?

शोध पद्धति

शोध प्ररचना

प्रस्तुत शोध अध्ययन में वर्णनात्मक शोध तथा अन्वेषणात्मक प्ररचना का प्रयोग किया जायेगा।

शोध समष्टि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आगरा नगर निगम में निवास करने वाले कुल अन्य पिछड़े वर्गीय परिवारों को शोध समष्टि के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

तथ्य संकलन के उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया जायेगा।

निदर्शन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में बहु–स्तरीय निदर्शन विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत प्रथम स्तर में आगरा नगर निगम के अन्तर्गत समस्त वार्डों में से 10 प्रतिशत वार्डों को देव निदर्शन विधि द्वारा चयन किया जायेगा। तदुपरान्त द्वितीय स्तर में चयनित वार्डों के मुहल्लों को सूचीबद्ध किया जायेगा एवं सूचीबद्ध मुहल्लों में से पिछड़े वर्गीय परिवारों की पहचान की जायेगी। तृतीय स्तर में सूचीबद्ध पिछड़े वर्गीय परिवारों में से पुनः देव निदर्शन विधि की सहायता से कुल 20 प्रतिशत परिवारों को निदर्शन के रूप में चयनित किया जायेगा जिसमें परिवार के मुखिया शामिल होंगे। निदर्शन चयन की प्रणाली को निम्नाकिंत रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है :–

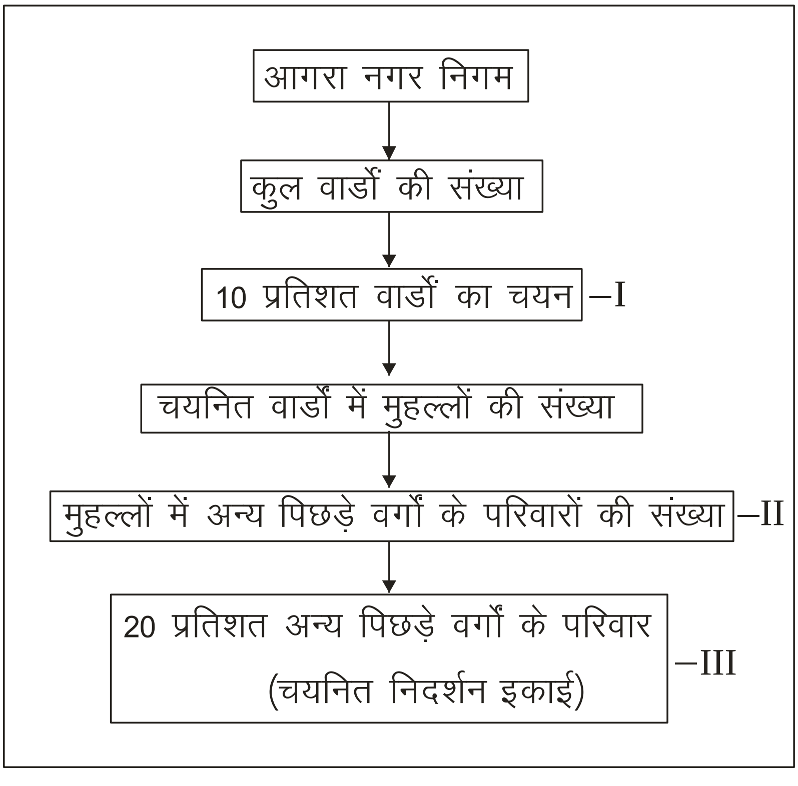

निदर्शन चयन की प्रणाली

तथ्य संकलन के स्रोत

प्रस्तुत शोध अध्ययन में तथ्य संकलन के स्रोत के रूप में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की सहायता से आंकड़ों का संकलन किया जायेगा। निदर्शन इकाईयों की प्रतिक्रिया (Responses) को प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत एवं सरकारी आंकड़ों एवं अभिलेखों को द्वितीय स्रोत के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

प्रस्तावित अध्याय

प्रथम अध्याय–

1.प्रस्तावना

2.सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

3.समस्या कथन

4.उद्देश्य

5.शोध प्रश्न

6.अध्ययन की पद्धति

7.अध्ययन का महत्व

द्वितीय अध्याय–

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : लैंगिक आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो का सशक्तीकरण।

तृतीय अध्याय–

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : आयु वर्ग के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो का सशक्तीकरण।

चतुर्थ अध्याय–

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : शैक्षिक आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो का सशक्तीकरण।

पंचम अध्याय–

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम : आय के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गो का सशक्तीकरण।

षष्ठम् अध्याय–

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तीकरण पर एक स्वॉट (SWOT) विश्लेषण।

सप्तम् अध्याय–

शोध अध्ययन की उपलब्धियाँ, निष्कर्ष एवं सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Biswas, Suprio (2016) Digital India : A Unique Step towards E-learning in India A Peer-Reviewed Monthly Research Journal, ISSN : 2394-7969 (Online), ISSN : 2394-7950 (Print) Volume-I, Issue-XII, January 2016, Page No. 64-70
- Shafiullah, Shaik (2016) : Digital India the Future of India, International Research Journal of Computer Science, Issue 12, Volume 3 (December 2016), ISSN : 2393-9842.
- Rodda, Jayamma (2016) : Digital India : Issues & Cure, International Research Journal of Computer Science, Issue 12, Volume 3 (December 2016), ISSN : 2393-9842.
- Khan, Saima (2015) :Digitization and its impact on Economy International Journal of Digital Library Services, Vol. 5, April-June 2015, Issue-2, ISSN : 2250-1142 (Online), ISSN : 2349-302X (Print).
- कुरूक्षेत्र (2016) : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली
- दृष्टिकोण मंथन : (2015) ई—गवर्नेंस, समाचार पत्र अर्द्धमासिक, नई दिल्ली
- आर. चन्द्रशेखर, 'स्मार्ट शहरों में डिजिटल गवर्नेंस' योजना (अगस्त 2015) : पत्रिका, भारत सरकार ।
- विजय कुमार पाण्डेय (2015) : 'साइनिंग डिजीटल इण्डिया', विज्ञान प्रगति सितम्बर (2015) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) नई दिल्ली पृ.सं. 13, 14
- फ्रैंकलिन, बी (2012) : संपादकीय, डिजिटल जर्नलिज्म, 1—5 (13 सितंबर 2014)
- योजना (नवम्बर 2014) : पत्रिका, भारत सरकार

- हिन्दुस्तान टाइम्स (2014, अप्रैल 24) : www hindustantimes.com/elections2014/election-beat/digital-democracy-who-is-winning-war-for-votes-on-twitter/article1-211958.aspx
- सिंह, एस (2014) : इंटरनेशल जर्नल ऑफ इनोवेशन इन द डिजिटल इकानॉमी 1–24
- Anand, Rimmi (2012) : E-Learning and Its Impact on Rural Areas, I.J Modern Education and Computer Science, 2012, 5, 46-52, Published Online June 2012 in MECS (http://www. mecs-press.org/)
- Sursh K. Chouhan, T. A. V. Murthy. (2012) “Digital divide and India” (PDF). Shodhganga@INFLIBNET Centre. P. 384. Retrieved 20 June 2012.